भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 392
05 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

भारी उद्योगों में डीकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देना

392. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्बन का अधिक प्रयोग करने वाले और विशिष्ट रूप से कार्बन आधारित भारी उद्योगों में डीकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा कार्बन का अधिक प्रयोग करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के बीच डीकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): वर्तमान में, भारी उद्योग मंत्रालय के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों ने कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए आंतरिक पहलें की हैं।

(घ): प्रमुख उपलब्धियां हैं:

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल)

बीएचईएल ने 1.4 टीपीडी कार्बन डाईऑक्साइड कैप्चर यूनिट के माध्यम से कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित करने के लिए अपने स्वदेशी समाधान का सफलतापूर्वक निदर्शन किया है जो एमिन-आधारित कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषण विधि का उपयोग कर रहे 0.25 टीपीडी कोयला-से-मेथनॉल निदर्शन संयंत्र के साथ एकीकृत है।

बीएचईएल द्वारा एनटीपीसी और आईजीसीएआर के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी (एयूएससी), सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्रों की तुलना में लगभग 11% तक कम कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन कर कोयला-आधारित बिजली उत्पादन में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ दक्षता प्रदान करती है।

बीएचईएल ने देश भर में फैली अपनी विनिर्माण इकाइयों में कुल 35 मेगावाट (लगभग) के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं।

भारतीय सीमेंट कॉर्पोरेशन (सीसीआई)

सीसीआई ने अपनी इकाइयों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए फ्लाई ऐश फीडिंग सिस्टम, हॉट एयर डक्ट, पुरानी मोटरों को बदलने की व्यवस्था की है।

*****